

मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज(होम)
भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी
वाणिज्यिक कर विभाग,
भरतपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, भरतपुर

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.पी.गुप्ता

अभिभाषक

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 53/RVAT/2014-15/अपी.प्राधि./भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बी, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2014 अन्तर्गत राजस्थान वेट कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के अन्तर्गत आरोपित ब्याज रुपये 3,66,254/- को विवादित करने पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार की है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2011-12 अवधि के लिए अर्ली रिफण्ड बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत श्रीमान् आयुक्त, वाणिज्यिक कर जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.10.06 (यथा संशोधित) की पालना में अर्ली रिफण्ड जारी किया गया। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी के स्वयं द्वारा निर्मित माल के अतिरिक्त क्रय किए तेल पर अर्ली रिफण्ड (Early Refund) देय होना नहीं मानते हुए अधिक राशि का अर्ली रिफण्ड जारी किये जाने से अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु 3,66,254/- आरोपित किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील अस्वीकार की गई जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवसायी तेल एवं खल का निर्माता है एवं तेल का क्रय विक्रय भी करता है। व्यवसायी

का निर्मित तेल हेतु क्रय किये गये कच्चे माल एवं तेल के क्रय पर 5 प्रतिशत की दर से चुकाये गये आगत कर आधिक्य का रिफण्ड चाहा गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अर्ली रिफण्ड इस आधार पर अस्वीकार किया कि आगत कर का क्लेम खाद्य तेल के क्रय कर पर किया है जो देय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी द्वारा निर्मित तेल के अतिरिक्त क्रय किये गये तेल पर लिये गये अर्ली रिफण्ड को अमान्य किया है जबकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.10.07 के अनुसार उत्पादित एवं क्रय किये गये तेल के विक्रय की दशा में भी अर्ली रिफण्ड देने के निर्देश हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने आयुक्त के परिपत्र के बावजूद भी तेल के क्रय विक्रय पर आगत कर के अर्ली रिफण्ड को अमान्य किया है जो विधिसम्मत नहीं हैं। अधिनियम 2003 की धारा 55 के अन्तर्गत अर्ली रिफण्ड अमान्य करने पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने विकल्प में यह भी कहा कि यदि अर्ली रिफण्ड नहीं देय होना मान भी लिया जाये तो भी प्राप्त किये गये अर्ली रिफण्ड पर ब्याज का निर्धारण अर्ली रिफण्ड ड्यू होने की तिथि तक लिया जाना चाहिए जबकि अपीलार्थी के प्रकरण में ब्याज कर निर्धारण आदेश पारित करने की दिनांक 26.03.14 तक आरोपित किया गया है। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पीटीशन न. 222/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम एम.एस. इन्स्ट्र्यूमेन्टेशन लि. कोटा में पारित निर्णय दिनांक 17.05.13 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। इन्होंने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है, अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि परिपत्र दिनांक 17.10.06 सरसों के तेल निर्माताओं के सम्बन्ध में है जिसमें तेल के व्यापार पर अर्ली रिफण्ड के कोई आदेश नहीं है। प्रार्थी सरसों का तेल निर्माता है जिस पर यह परिपत्र लागू होता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. अपीलार्थी व्यवसायी सरसों तेल का विनिर्माता है तथा तेल का क्रय विक्रय भी करता है। प्रकरण में अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2011-12 अवधि के लिए अर्ली रिफण्ड बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत श्रीमान् आयुक्त, वाणिज्यिक कर जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र की पालना में उत्पादित तेल के अलावा व्यवहारी द्वारा तेल के क्रय विक्रय से सम्बन्धित संव्यवहार पर भी अर्ली रिफण्ड जारी किया गया। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी के स्वयं द्वारा निर्मित माल के अतिरिक्त क्रय किए तेल पर अर्ली रिफण्ड (Early Refund) देय होना नहीं मानते हुए अधिक राशि का अर्ली रिफण्ड जारी किये जाने से अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु 3,66,254/- आरोपित किया गया।

8. विचाराधीन प्रकरण में अधिनियम 2003 की धारा 17(2) व परिपत्र दिनांक 17.10.2006 एवं परिपत्र दिनांक 26.10.2007 का उल्लेख करना समीचीन है :-

(1) धारा 17(2) Taxpayable by a dealer - (1) XXX

(2) Where the net tax payable under sub-section (1) has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act and the balance amount if any, shall be

carried forward to the next tax period or periods. In case of the dealer claims refund of the balance amount, if any, at the end of the years, the same shall be granted only after the end of the immediately succeeding year however the commissioner after recording reason for doing so may, be a general or specific order, direct to grant such refunds even earlier.]

(2) परिपत्र S.No. 2146 F.16(327) Tax/VAT/CCT/06/1696 दिनांक 17.10.2006

Oil seed, edible oil and oil-cake (except cotton seed oil cake) are taxable at the rate 4% in the State. Whereas, the rate of CST on sale of the mustard oil manufactured in the State is 1% under Sub-section (5) of section 8 of CST Act, 1956. Oilcake (including cotton seed oil cake) attracts 4% tax on its inter-State sales and de-oiled cake is exempt both in inter-State and intra-State sales.

Substantial part of the mustard oil manufactured in the State is being sold in the course of inter-State trade of commerce. In such cases, the net tax payable by the mustard oil manufacturers of the State, has a negative value, such dealers are entitled to get refunds of the excess amount of tax paid on mustard seed. As per the provisions of sub-section (2) of section 17 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 any refund has to be made only after the end of the immediately succeeding year, after first adjusting the same against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act. However, the Commissioner after recording reasons for doing so may, by a general or a specific order, direct to grant such refunds even earlier.

The representative Associations of the mustard oil manufacturers have requested that in the present scenario, substantial amount of their working capital is getting locked up, resulting in adverse impact on their business, therefore, early refunds may be granted.

Keeping in view the fact that mustard oil industry has a vital role in the economy of the State, early grant of refunds would facilitate this sector. In view of this it appears rational and appropriate that the mustard oil manufacturers may be granted early refunds as per the provisions of sub-section (2) of section 17 of the Act. It is, therefore, directed that where the net tax payable for any quarter has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act, the claimant registered dealer manufacturing mustard oil exclusively shall submit an application in Form-A appended hereunder, to the assessing authority for the remaining amount, along with the following documents:-

1. Self attested copies of purchase VAT invoices, on basis of which refund is being claimed.
2. Declaration of the registered dealer issuing above referred VAT invoice(s) in Form-B appended hereunder, the goods have been sold by him to the dealer claiming refund on their basis, along with details of deposit of VAT in the Government treasury regarding such sales.
3. Self attested copies of the sale(VAT) invoices.

206

लगातार.....4

4. An undertaking attached to Form-A by the dealer claiming early refunds, that in case it is found that the full tax leviable on mustard oil seed under the Act, has not been paid to the State Government at any of the earlier stages, he undertakes to deposit such amount refunded to him along with the interest at the rate notified by the State Government under section 55 of the RVAT Act, 2003, within ten days of the receipt of notice from the assessing authority.

5. Security equal to the amount to be refunded, in any form as prescribed under rule 77 of the Rajasthan VAT Rules, 2006, to the satisfaction of the assessing authority, to make payment of the refunded amount, in case such amount is not found deposited in the State treasury or refund has been found to be in excess of the refund due under the Act.

6. Certificate of Chartered Accountant as to the correctness of claim of refund in Form-C. The Claim of concessional rate of tax will be limited to the extent of the declaration forms furnished by the dealer at the time of filing of the relevant return.

in view of the above reasons, it is hereby directed that all assessing authorities, after having been satisfied with genuineness of the transactions and the relevant documents, shall dispose of the application of the mustard oil manufacturers claiming early refunds within a period of thirty days from the date of submitting completed application in Form-A along with the above specified documents in the following manner :-

(i) The assessing authority shall pass speaking order, Where refund is allowed partially or disallowed, the applicant shall be afforded opportunity of being heard before passing such order.

(ii) Where the refund in part or in full is allowed, he shall issue refund order to the applicant in the manner specified under the Rajasthan VAT Rules, 2006.

(iii) Where the mustard oil has been manufactured by the unit taken on rent/lease, early refund shall be allowed to the extent of 75% of the refundable amount. However, refund of remaining amount of 25% shall be granted on furnishing of a bank guarantee valid for the period upto 31st March of the succeeding year, payable by a branch of Nationalized Bank situated in the State.

(iv) Subsequent to the passing of such order, if it is found that refund was granted in excess of the actual refund due, such excess refunded amount shall be recovered as if it is a tax due from the dealer under this Act and the interest on such tax shall be charged at the rate notified by the State Government under section 55 of the RVAT Act, 2003 for the period from the date of grant of refund, till the date such amount is paid to the Government treasury.

(v) A separate register shall be maintained by each assessing authority for all the applications received for early refund and action taken thereon.

In cases where refunds have been issued, the assessing authority should take steps on priority basis to finalize the pending assessments of such dealers, to verify the transactions upto the first point in the series of sales, on the basis of which refund has been claimed, to ensure actual deposit of tax so refunded, and to get verified the declaration forms submitted by the dealer in support of concessional rate of tax.

(3) परिपत्र No. F. 16(327) Tax/VAT/CCT/06/1693 दिनांक 26.10.2007

CIRCULAR

Sub: Regarding early refunds to the oil manufacturers of the State.

Oil seeds, Edible oil and oil-cake (except cotton seed oilcake) are taxable at the rate of 4% in the State whereas the rate of CST on sale of edible oil manufactured in the State is 2% under sub-section (5) of section 8 of CST Act, 1956, Oil-cake (including cotton seed oil-cake) is taxable at the rate of 3% under Center Sales Tax Act, 1956 and de-oiled cake is exempt from tax both under RVAT Act, 2003 and CST Act, 1956.

2m

लगातार.....5

Major sale of oil manufactured in the State takes place in the course of inter-State trade or commerce. In cases where the raw material is purchased from dealers registered in the State, the net tax payable by the manufacturers of oil has a negative value. such dealers are entitled to get refund of the excess amount paid on purchases of oil seeds. As per provisions of sub-section (2) of section 17 of the RVAT Act, 2003, any refund has to be made only after the end of the immediately succeeding year, after first adjusting the same against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act, No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act. However, the Commissioner, after recording reasons for doing so may, by a general or a specific order, direct to grant such refunds even earlier.

Directions for early refunds to mustered oil manufacturers were issued earlier. The representative Associations of the manufacturers of oil have also requested for early refunds, for the oil manufacturers manufacturing groundnut oil, cotton seed oil and castor oil in the State, as substantial amount of their working capital is blocked resulting in adverse impact on their business. It has also been requested that refund should not be withheld where the manufacturers have affected some sales of goods other than oil manufactured by them. Keeping in view the genuine hardship of the such dealers may be granted early refunds as per the provisions of sub-section (2) of section 17 of the Act. It is, therefore, directed that where the net tax payable for any quarter has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act, and for the remaining amount the claimant registered dealer manufacturing oil within the State shall submit an application for early refund in Form-A appended hereunder, to the assessing authority, along with the following documents:-

1. XXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXX

The Claim of concessional rate of tax will be limited to the extent of the declaration forms furnished by the dealer.

In view of the above, it is hereby directed that all assessing authorities, after having been satisfied with the genuineness of the transactions and the relevant documents, shall dispose of the application claiming early refunds of the manufacturers of oil, manufacturing oil in the State, within a period of thirty days from the date of submitting completed application in Form-A along with the above specified documents in the following manner:-

- (i) The assessing authority shall pass speaking order, Where refund is allowed partially or disallowed, the applicant shall be afforded opportunity of being heard before passing such order.
- (ii) Where the refund in part or in full is allowed, he shall issue refund order to the applicant in the manner specified under the Rajasthan VAT Rules, 2006.
- (iii) Where the oil has been manufactured by the unit taken on rent/lease, early refund shall be allowed to the extent of 75% of the refundable amount. However, refund of remaining amount of 25% shall be granted on furnishing of a bank guarantee valid for the period upto 31st March of the succeeding year, issued by a branch of Nationalized Bank situated in the State.
- (iv) Subsequent to the passing of such order, if it is found that refund was granted in excess of the actual refund due, such excess refunded amount shall be recovered as if it is a tax due from the dealer under this Act and the interest on such tax shall be charged at the rate notified by the State Government under section 55 of the RVAT Act, 2003 for the period from the date of grant of refund, till the date such amount is paid in the Government treasury.

2/2

लगातार.....6

- (v) A separate register shall be maintained by each assessing authority for all the applications received for early refund and action taken thereon.

In cases where refunds have been issued, the assessing authority should take steps on priority basis to finalize the pending assessments of such dealers, to verify the transactions upto the first point in the series of sales, on the basis of which refund has been claimed, to ensure actual deposit of tax so refunded, and to get verified the declaration forms submitted by the dealer in support of concessional rate of tax.

It should be ensured that no undue hardship is caused to the applicants and the applications are disposed of within the stipulated time. The Deputy Commissioner (Adm.) shall monitor the cases for such refunds. Additional commissioners shall also review a few cases of such refunds during their visits to the officers.

(4) धारा- 55 :- Interest on failure to pay tax or other sum payable - (1) XXXXXXXX

(2) XXXXXXXX

(3) XXXXXXXX

(4) Where a dealer, registered under this Act, has wrongly availed input tax credit or has been granted an erroneous refund in any manner, such dealer shall be liable to pay interest at such rate as may be notified by the State Government from time to time, on the amount wrongly availed credit or the amount of such refund as the case may be and such interest shall be calculated from the first day of the month succeeding the month in which the credit was wrongly availed or the refund was erroneously granted till the day on which such payment is made.

9. विचाराधीन प्रकरण में प्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि परिपत्र दिनांक 17.10.2006 एवं 26.10.2007 के संदर्भ में प्रार्थी जो कि सरसों के तेल का विनिर्माता होने के साथ-साथ तेल का व्यापार भी करता है, को इनपुट टैक्स का अर्ली रिफण्ड (Early Refund) देय है या नहीं। अधिनियम 2003 की धारा 17(2) के अनुसार अधिशेष बचे टैक्स का रिफण्ड वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 1 वर्ष के पश्चात् देय होता है परन्तु आयुक्त ऐसा रिफण्ड पहले दिये जाने हेतु अधिकृत हैं। सरसों के तेल विनिर्माताओं की एसोसिएशन के ज्ञापन के आधार पर आयुक्त द्वारा परिपत्र दिनांक 17.10.2006 जारी किया गया है जिसमें सरसों तेल विनिर्माताओं का अर्ली रिफण्ड दिये जाने का प्रावधान किया गया है। तेल विनिर्माताओं की एसोसिएशन द्वारा पुनः ज्ञापन देकर यह माग करने पर कि ग्राउण्ड नट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल व केस्टर ऑयल निर्माताओं को भी अर्ली रिफण्ड दिया जावे व रिफण्ड इस आधार पर नहीं रोका जावे कि विनिर्माताओं द्वारा कुछ ऐसे तेल का विक्रय किया गया है जो उनके द्वारा उत्पादित नहीं है, आयुक्त द्वारा परिपत्र दिनांक 26.10.07 जारी किया गया है। परिपत्र दिनांक 26.10.07 में भी अर्ली रिफण्ड के आदेश अन्य तेल निर्माताओं के सम्बन्ध में है परन्तु इस परिपत्र दिनांक 26.10.07 में इस बिन्दु का कोई उल्लेख नहीं है कि उत्पादित तेल के साथ-साथ तेल के क्रय विक्रय से सम्बन्धित संव्यवहार पर भी अर्ली रिफण्ड देय होगा। परिपत्र दिनांक 17.10.06 में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार द्वितीय ज्ञापन में एसोसिएशन द्वारा माग की गई है कि विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 17.10.06 का लाभ उन तेल निर्माताओं को नहीं दिया जा रहा जो स्वयं द्वारा उत्पादित

20/11

लगातार.....7

तेल के साथ-साथ क्रय किये गये तेल का व्यापार भी करते हैं तथा ऐसे तेल निर्माताओं को भी अर्ली रिफण्ड दिया जाना चाहिए। विद्वान आयुक्त द्वारा भी जो परिपत्र दिनांक 26.10.07 जारी किया गया है उसमें इसी संदर्भ में अर्ली रिफण्ड दिये जाने का उल्लेख है परन्तु इस परिपत्र में क्रय किये गये तेल के संव्यवहार पर अर्ली रिफण्ड दिये जाने का कोई आदेश नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कुछ तेल निर्माताओं को उत्पादित तेल के साथ-साथ तेल के क्रय विक्रय पर भी अर्ली रिफण्ड दिया जाता है तो फिर सिर्फ तेल के व्यापार करने वालों को इसका लाभ क्यों नहीं वरन् तेल के व्यापार करने वालों को इसका लाभ दिया जाता है तो अन्य प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारियों को क्यों नहीं। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार दोनों ही परिपत्रों में तेल के क्रय विक्रय पर अर्ली रिफण्ड का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि मात्र उत्पादित तेल से सम्बन्धित संव्यवहार पर ही अर्ली रिफण्ड देय है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में यह ठहराया गया है कि परिपत्र की व्याख्या सामान्य तौर (General Term) सामान्य तौर पर की जानी चाहिए न कि विशिष्ट तौर पर। अपीलार्थी को इस न्यायिक दृष्टांत से कोई बल नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही परिपत्रों में स्पष्ट प्रावधान है जिनकी व्याख्या का कोई बिन्दु नहीं है।

10. विचाराधीन प्रकरण में द्वितीय विचारणीय बिन्दु यह है कि अधिनियम 2003 की धारा 55 में अर्ली रिफण्ड से सम्बन्धित मामलों में ब्याज का आरोपण किया जा सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 55(4) का उल्लेख करना समीचीन है :-

55. Interest on failure to pay tax or other sum payable. - (1) Where any person or a dealer commits a default in making the payment of any amount of -

(4) Where a dealer, registered under this Act, has wrongly availed input tax credit or has been granted an erroneous refund in any manner, such dealer shall be liable to pay interest, at such rate as may be notified by the State Government from time to time, on the amount of wrongly availed credit or the amount of such refund as the case may be and such interest shall be calculated from the first day of the month succeeding the month in which the credit was wrongly availed or the refund was erroneously granted till the day on which such payment is made.

उपरोक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि किसी भी प्रकार से रिफण्ड में कोई त्रुटि हुई है तो ऐसे रिफण्ड पर ब्याज देय है तथा विचाराधीन प्रकरण में अर्ली रिफण्ड देय नहीं होने के बावजूद भी दे दिया गया है तो यह त्रुटि कारित रिफण्ड है

11. विचाराधीन प्रकरण में तृतीय विचारणीय बिन्दु यह है कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किये गये अर्ली रिफण्ड पर ब्याज किस तिथि तक आरोपित किया जाना चाहिए। अपील के अनुसार प्रकरण वित्तीय वर्ष 2011-12 का है जिसका नियमानुसार रिफण्ड अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार आगे के वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति के तत्काल

27/

लगातार.....8

पश्चात् अर्थात् 01.04.2013 को देय है। इस प्रकार अर्ली रिफण्ड की राशि पर 01.04.13 से पूर्व की तिथि अर्थात् 31.03.13 तक तक ब्याज का आरोपण किया जाना चाहिए तथा उसके पश्चात् ब्याज का आरोपण नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तिथि के पश्चात् अपीलार्थी रिफण्ड का नियमानुसार पात्र था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.14 को पारित किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अर्ली रिफण्ड पर ब्याज का आरोपण 26.03.14 तक किया गया है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य हैं।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उत्पादित तेल पर ही अर्ली रिफण्ड देय है तथा क्रय किये गये तेल से सम्बन्धित संव्यवहार पर अर्ली रिफण्ड देय नहीं है व धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज का आरोपण विधिसम्मत है। साथ ही अर्ली रिफण्ड पर ब्याज का आरोपण 31.03.13 तक ही किया जाना चाहिए। फलतः अपील प्रथम दो बिन्दुओं पर अस्वीकार एवं तृतीय बिन्दु पर स्वीकार की जाती है। करण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अर्ली रिफण्ड पर ब्याज की गणना नियमानुसार उपरोक्तानुसार की गई विवेचना के अनुसार पुनः करें। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.03.2018 को उपस्थित हो।

13. निर्णय सुनाया गया।

(नैथूराम)
सदस्य